

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

[८१६६४]

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-२

देहरादून : दिनांक २/ जून, २०१७

विषय- १३वें वित्त आयोग की संस्तुति के अंतर्गत देहरादून शहर की मल व्ययन योजना हेतु रू० १०.०० करोड राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या १७८३/नियो०अनु०-धनावंटन प्रस्ताव/११९ दिनांक २३ नवम्बर, २०१६ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें १३वें वित्त आयोग के अंतर्गत देहरादून शहर की मल व्ययन योजना हेतु पुनरीक्षित आगणन रू० १९०.६४ करोड के विरुद्ध १२४.१८ करोड की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए रू० ६६.४६ करोड की धनराशि अवमुक्त किया जाना है।

२- उक्त के क्रम में योजना की पूर्व में अनुमोदित लागत रू० १७०.४६ करोड की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए अब तक निम्नलिखित शासनादेशों द्वारा कुल रू० १२४.१८ करोड की धनराशि अवमुक्त की गयी है:-

क्र०सं०	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	धनराशि लाख में स्वीकृत धनराशि
१	७०/उन्तीस(२)/१३-२(४५पे०)/२०११ दिनांक १५ जनवरी, १३	१८७४.००
२	९९५/उन्तीस(२)/१४-२(४५पे०)/२०११ दिनांक २९ सितम्बर २०१४	४४०५४४
३	६३/उन्तीस(२)/१५-२(४५पे०)/२०११ दिनांक ०४ फरवरी, २०१५	१६९४.५६
४	५५८/उन्तीस(२)/१५-२(४५पे०)/२०११ दिनांक ३१ मार्च, २०१५	४४४४.००
	योग	१२४१८.००

३- उपरोक्त योजना को शासनादेश संख्या- ७६२ / उन्तीस (२) / १५ -२ (४५पे०)/२०११ दिनांक ०८ जनवरी, २०१६ के माध्यम से पुनरीक्षित करतै हुए रू० १९०.६४ करोड की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान की गयी।

४- अतः देहरादून सीवेज योजना हेतु पुनरीक्षित लागत रू० १९०.६४ करोड के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू० १२४.१८ करोड को कम करते हुए अवशेष धनराशि रू० ६६.४६ करोड की धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष, २०१७-१८ में रू० १०.०० करोड की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से व्यय करने हेतु निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपके निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

- (ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।
- (iii) प्रतिमाह के अन्त में व्यय विवरण बी0एम0-13 पर एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा किये गये कार्यों का प्रगति विवरण नियमित रूप से शासन को अविलम्ब 20 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जायेगा और महालेखाकार से समय-समय पर आंकड़ों का मिलान सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iv) राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृति धनराशि के समायोजन/प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2017-18 में कर लिया जायेगा।
- (v) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ़ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
- (vi) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
- (vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।
- (viii) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जायेगी एवं कार्यदायी संस्था के रूप में प्रबन्ध निदेशक इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (ix) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का निरीक्षण भली भाँति अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
- (x) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।
- (xi) उक्त योजना के कार्य उत्तरखण्ड अधिपति नियमवली, 2008, वित्त नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायक नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्यय सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल), तथा अन्य सुसंगम नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (xii) मुख्य सचिव, उत्तरखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 2047/xiv-219(2006) दिनांक 30 मई, 2016 द्वारा निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (xiii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।
- (xiv) सर्वप्रथम एस0टी0पी0 के निर्माण कार्य पूर्ण कराये जायेंगे तथा एस0टी0पी0 के दायित्वों हेतु धनराशि पहले व्यय की जायेगी। सीवररेज कार्यों/लाईनों का उन्ही का भुगतान किया जाय, जो एस0टी0पी0 से जुड़ गये हों तथा जनता को तत्काल सीवर व्यवस्था का लाभ प्राप्त हो रहा हो।
- (xv) ऐसे सीवररेज नेटवर्क का भुगतान कदापि न किया जाय, जो मुख्य सीवररेज नेटवर्क से कनेक्ट नहीं है तथा तत्काल उपयोग में लायी जानी संभव नहीं है। इस हेतु कार्य के प्रभारी अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रथमतः-8000-राज्य आकस्मिकता निधि-201-समेकित निधि के विनियोजन के नामे डाला जायेगा, अन्ततः अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

6- धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवटन संख्या F 1706990024 दिनांक 21 जून, 2017 से आवटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या 312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31 मार्च, 2017 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 111 /XXVII(2)/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)

अपर सचिव

पू0सं0 14 (1)/xxvii(1)/रा0आ0क0निधि/2017 दिनांक 20 जून, 2017

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी- प्रथम) उत्तराखण्ड आबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

ह0

(श्रीधर बाबू अददांकी)

अपर सचिव

पू0सं0 14 (1)/अन्तीस(2)/17-2(45पे0)/2011 तददिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2-जिलाधिकारी, देहरादून।
- 3-वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
- 4-बजट निदेशालय, देहरादून।
- 5-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-02
- 6-मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
- 7-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(निर्मल कुमार)

अनु सचिव